उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 06 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(09/19)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) सुमाडी, श्रीनगर के स्थायी कैम्पस निर्माण सम्बन्धी बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों से एन.आई.टी. श्रीनगर के भूमि चयन, प्रस्तावित भवन निर्माण सम्बन्धी सभी तथ्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एन.आई.टी. श्रीनगर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका निर्माण सुमाडी, श्रीनगर में पूर्व चयनित स्थान पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वंय सभी तथ्यों के साथ भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर एन.आई.टी. का कैम्पस निर्माण शीघ्र शुरू कराने का अनुरोध करेंगे।

बैठक में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि एन.आई.टी. सुमाडी श्रीनगर को लेकर उनकी स्वयं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से वार्ता हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एन.आई.टी. के स्थायी कैम्पस का निर्माण सुमाड़ी श्रीनगर में ही होगा।

निदेशक, तकनीकि शिक्षा डा0 पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि पिछले वर्षों में एन0आई0टी0 के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था एन0बी0सी0सी0 द्वारा जो भी स्टडी की गई वो सभी सकारात्मक है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में गठित साइट सेलेक्शन कमेटी ने भी एन.आई.टी श्रीनगर हेतु सुमाड़ी में चयनित भूमि को उपयुक्त माना है। इसके बाद ही एच.आर.डी. मंत्रालय ने एनबीसीसी को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया। डॉ.पाण्डेय ने यह भी बताया कि एन.आई.टी. श्रीनगर की भूमि कैम्पस निर्माण अनुपयुक्त होने की कोई अधिकारिक सूचना राज्य सरकार को कभी नही दी गई और न ही कभी राज्य सरकार का पक्ष जानने का प्रयास किया गया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, रजिस्ट्रार एन.आई.टी. कर्नल सुखपाल सिंह, जिलाधिकारी पौड़ी श्री सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 06 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(09/18)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, सांसद श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज एवं श्री प्रकाश पंत के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस महत्वकांक्षी परियोजना के बारे में देश एवं राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्य योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजने पर चर्चा की गई। पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए पुनर्वास, विस्थापन, सर्किल रेट, विभागीय परिसम्पतियों एवं सार्वजनिक स्थानों का शासन स्तर पर आकलन एवं आंगणन कर पूर्ण कार्ययोजना बनाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि परियोजना से जो भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए एवं जन सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के हित को देखते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। जिससे केन्द्र सरकार से सभी मुद्दों पर गहनता से विचार–विमर्श किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी बहुद्देशीय परियोजना के अनुभवों को भी ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के लिए डी.पी.आर बनाई जाए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव सिंचाई श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, सिंचाई, पेयजल एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून 06 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(09/17)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में समाधान पोर्टल हेतु स्मार्ट आई.वी.आर.(इंटरैक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स) सिस्टम के माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों को मोबाईल/दूरभाष पर प्राप्त कर उनका निस्तारण किये जाने सम्बन्धी सेवा का शुभारम्भ किया। जन समस्याओं और सुझावों को और अधिक सुगम बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नम्बर 1905 पर फोन कर अपनी शिकायत या सुझाव को पंजीकृत करा सकते है। इसके लिए शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं शिकायत का विवरण देना होगा। शिकायत एन.आई.सी. के पोर्टल पर दर्ज हो जायेगी। उसके बाद शिकायत, सम्बन्धित विभाग को भेजी जायेगी। जिसका सम्बन्धित विभाग द्वारा 10 दिन के अन्दर फीडबैक दिया जायेगा। आईवीआर सिस्टम के तहत एक साथ 15 लोग शिकायत/सुझाव दर्ज करा सकते हैं। इसमें लोग स्थानीय भाषा में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिसके लिए अनुवाद की व्यवस्था भी रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि समाधान पोर्टल पर आई.वी.आर. सिस्टम के होने से जनसमस्याओं के निवारण में तेजी आयेगी। समस्याओं के निवारण के लिए सम्बन्धित विभागों की जिम्मेदारी तय रहेगी। इससे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं पहुंचेगी तथा सुझाव भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अच्छी बात है कि आई.वी.आर. सिस्टम में स्थानीय बोलियों को भी सम्मिलित किया गया है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रकाश पंत, अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री डी.सेन्थिल पाण्डियन, श्री हरबंस सिंह चुघ, श्री चन्द्रशेखर भट्ट, गढ़वाल कमिश्नर श्री दिलीप जावलकर, महानिदेशक सूचना डॉ.पंकज कुमार पाण्डेय आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।